

भारत सरकार  
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या - 102  
सोमवार, 25 नवम्बर, 2024/4 अग्रहायण, 1945 (शक)

नई आईटीआई उन्नयन योजना का कार्यान्वयन

102. श्री जी. लक्ष्मीनारायणः  
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए एक नई योजना शुरू की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के विशिष्ट उद्देश्य क्या है;
- (ख) इस योजना के अंतर्गत जिन आईटीआई का उन्नयन किया जाने का प्रस्ताव है उनकी संख्या कितनी है तथा विशेषकर अवसंरचना पेशकश किए गए पाठयक्रमों और उद्योगों की अवसंरचना आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के विशेष संदर्भ में उन्नयन के लिए आईटीआई को चुने जाने के क्या मानदंड हैं;
- (ग) क्या यह योजना सुनिश्चित करेगी कि उन्नयन किए गए आईटीआई राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में कौशल की मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वचालन जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) आईटीआई उन्नयन योजना के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार युवाओं के कौशल और रोजगार परिणामों पर उन्नयन किए गए आईटीआई के प्रभाव की निगरानी और आकलन करेगी, यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;
- (च) क्या आंध्र प्रदेश में आईटीआई उन्नयन पहल के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में इस योजना से लाभान्वित होने वाले आईटीआई की संख्या कितनी है; और
- (छ) क्या यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि उन्नयन किए गए आईटीआई राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में कौशल की मांग को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और स्वचालन जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) जी, हां। केंद्रीय बजट 2024 में प्रधानमंत्री कौशल पैकेज के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। इस योजना का उद्देश्य राज्य

सरकारों और उद्योग के सहयोग से परिणाम उन्मुखीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए हब-एंड-स्पोक व्यवस्था के माध्यम से 1,000 आईटीआइज का उन्नयन करना है। इसमें प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए पांच राष्ट्रीय संस्थानों की क्षमता वृद्धि भी शामिल है।

(ख) केंद्रीय बजट 2024 की घोषणा के अनुसार इस योजना के तहत 1,000 आईटीआइज को अपग्रेड किया जाना है। आईटीआइज का चयन उद्योग भागीदारों के परामर्श से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) प्रस्तावों के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

(ग) जी, हां। इस योजना के तहत पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने का प्रस्ताव है और उभरती मांगों को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।

(घ) यह योजना पांच साल की अवधि के लिए प्रस्तावित है।

(ई) जी, हां। योजना की अवधि के दौरान मूल्यांकन अध्ययनों और क्षेत्रीय अध्ययनों के माध्यम से उन्नत आईटीआइज के प्रभाव की निगरानी करने का प्रस्ताव है।

(च) जी, नहीं। योजना के तहत अदिनांक किसी भी राज्य को कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(छ) जी, हां। योजना के तहत, मौजूदा पाठ्यक्रम सामग्री और डिजाइन को उद्योग की कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने का प्रस्ताव है और उभरती मांगों को पूरा करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

\*\*\*\*\*